

विचार-मंथन

हमारी प्रतिक्रियाएं संयमित और मापी जानी चाहिए।
एक मुहा है जिससे दोनों पक्षों को सावधानीपूर्वक
निपटने की आवश्यकता होती। यह भारतीय सुरक्षा
एजेंसियों से जुड़े होने के सदैव बाले व्यक्तियों द्वारा
कनाडा और अमरीका में खालिस्तानी तत्वों की
हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों से संबंधित है।

अमरीकी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से इस
मुहे से निपटना अब जटिल हो गया है। इसे उस
सांझेदारी पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी
चाहिए जो अनिश्चित और अप्रत्याशित दुनिया में

भू-राजनीतिक आधार बन गई है।

कमला हैरिस को औपचारिक रूप से नवबर
में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए
डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार नियुक्त
हैरिस होनी जो 'राष्ट्रपति पद के लिए तैयार
नहीं थी' और 'डोनाल्ड ट्रम्प को रोक नहीं
सकती थीं। चुनावों में आसान जीत से
परिवर्तित को चिह्नित करता, जो मौजूदा
राष्ट्रपति जो बाइडेन के तहत एक नियम और
पैदल चलने वाली राजनीतिक शिक्षण और
और ज्यादातर अद्युत उप-राष्ट्रपति के रूप
में उनकी छवि को तोड़ देता। एक बार जब
बाइडेन अपनी पार्टी में बोडे सह ट्रम्प के
उम्मीदवार के रूप में उनका त्वरित और
नियोरेश समर्थन अप्रत्याशित था। उनके
अभियान में नक्ती की जो बाढ़ अपनी सुरु
हुई वह लगभग शानदार थी। हफ्तों तक
बाइडेन प्रशासन के अंदरूनी सूझों ने इस बात

अमरीकी चुनाव में बदलाव और भारत

पर जो दिया था कि राष्ट्रपति को दूसरे
कार्यकाल के लिए प्रयास करना होगा क्योंकि
उनके स्थान पर अनुपस्थित प्रसंग कम्यून
हैरिस होनी जो 'राष्ट्रपति पद के लिए तैयार
नहीं थी' और 'डोनाल्ड ट्रम्प को रोक नहीं
सकती थीं। चुनावों में आसान जीत से
परिवर्तित को चिह्नित करता, जो मौजूदा
राजनीतिक शिक्षण और अप्रत्याशित उम्मीदवार
में बोडे से आगे चल रहा है। उन्होंने पूरे
देश में एक अच्छा मौलिं पैदा किया है और
अभियान के लिए बचे 6 हफ्तों में किसी भी
गंभीर गलत कदम को छोड़कर, वह अमरीका
की आगे चल गए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के
उम्मीदवार के रूप में उनका त्वरित और
नियोरेश समर्थन अप्रत्याशित था। उनके
अभियान में नक्ती की जो बाढ़ अपनी सुरु
हुई वह लगभग शानदार थी। हफ्तों तक
कमला हैरिस को अधिकांश

लोगों के लिए कमला हैरिस का अमरीकी
राष्ट्रपति बनना एक बड़ी राहत की अनुभूति
लेकर आएगा। भारत में, किसी ने उम्मीद भी
नहीं की होगी कि एक अमरीकी कम्यून
नेता का डोस्टीनीय उम्मीद, जो उतना ही
भारतीय-अमरीकी है जितना कि वह अखेत
अमरीकी है, अब तक प्रविति होने की
कुलन में कहीं अधिक रुचि और आत्मीयता
की भावना पैदा करेगा। विदेशों में भारतीय
मूल के लोगों की सफलता का जशन मात्र
द्वारा गवर्नर की अधिकारिताएं अवश्य सुनी
जाती हैं। भारत में उनके प्राचीनिक सर्वोच्च
महाने न्यून्यत में भवित्व के लिए संस्कृत
ग्रन्थ विद्या सम्मेलन के लिए एक प्रभुत्व है। अमरीका भारत के
लिए एक प्रभुत्व वाला बना हुआ है जिसके
सेवा क्षेत्र में, और अमरीकी पूरी प्रवाह भारत
की विकास कहानी में एक महत्वपूर्ण कारक
बन गया है। जब वे भारत की अमरीका में
राष्ट्र-विद्या सम्मेलन के लिए एक संघीय
अपीली आगामी यात्रा के दौरान प्राचानमंडी
नंदेंद्र भौमी सुधी हैरिस से जुड़ने का अवसर
राजनीतिक व नागरिक समाज की भागीदारी
के माध्यम से घोषित किया जाना चाहिए। और सभी
अगले साल जनवरी में जो भी प्रशासन

कार्यभार संभालेगा, भारत को उससे निपटना
होगा। ट्रम्प के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक
दोस्टों के बीच समग्र रणनीतिक
अभिसरण बरकरार है। दोस्टों में से कोई नहीं
चाहत कि डोनाल्ड-प्रसाद क्षेत्र पर जीवन का
प्रभुत्व हो। बिकास के अपने वर्तमान चरण
में, नागरिक और रक्षा दोस्टों बीच में
अल्पाधिक अमरीकी प्रौद्योगिकी का भारत
की पूर्वुच महत्वपूर्ण है। अमरीका भारत के
लिए एक प्रभुत्व वाला बना हुआ है जिसके
सेवा क्षेत्र में, और अमरीकी पूरी प्रवाह भारत
की विकास कहानी में एक महत्वपूर्ण कारक
बन गया है। जब वे भारत की अमरीका में
राष्ट्र-विद्या सम्मेलन के लिए एक संघीय
अपीली आगामी यात्रा के दौरान प्राचानमंडी
नंदेंद्र भौमी सुधी हैरिस से जुड़ने का अवसर
लताश। पिछले एक दशक में भारत-
अमरीका संबंधों ने अभूतपूर्व विस्तार और
जैसा कि अतीत में होता रहा है।

सरकार बार-बार बैकफूट पर क्यों



मोदी-शाह जानते हैं कि उनके मजबूत सहयोगी जे.डी.यू. और टी.डी.पी. अपने-अपने राज्यों में कहाँ सेक्युरिटी समर्थकों के विरोध नहीं ले रहे। फिरसे उन्होंने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के लिए बाबू देखना किया जाएगा। इसका पक्ष-विपक्ष ने विरोध किया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने संसद संसद तक देखना किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के द्वितीय बड़े अंदर और बाहर दोनों राज्यों में लगातार जारी है। इनका सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार-बार बैकफूट पर आ जाना चाहिए। इसी अपने राजनीतिक शिक्षण के ल

